योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन ने भास्कर से की बातचीत

राज्य का अपेक्षित विकास नहीं हुआ : अभिजीत सेन

भास्कर संवाददाता | रांची

झारखंड का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। जबकि बिहार ने कृषि क्षेत्र में अच्छा विकास किया है। झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा यहां स्थाई सरकार का नहीं होना है। स्थाई सरकार होगी, तो स्थाई विकास की योजनाएं भी बनेंगी। इन 14 सालों में झारखंड का यह दुर्भाग्य रहा कि यहां की जनता ने किसी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। ये बातें योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन ने भास्कर से बात करते हुए कही। सेन बुधवार को राजधानी में एक सेमिनार में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में मिनरल्स अधिक है, लेकिन इसका फायदा यहां के आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। मिनरल्स का उपयोग एक वर्ग की कर रहा है। सेन ने कहा कि कृषि आधारित योजना से राज्य का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग भंग किया गया है, लेकिन उसके कार्य तो होने ही हैं। 1952 में योजना आयोग का गठन कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर किया गया था। अब 2014 में केंद्र सरकार पुनः कोई एक्ट पास कर योजना आयोग के जिम्मे कार्य का बंटवारा कर देगी। उन्होंने कहा कि योजना आयोग को असफल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरा सफल रहा है यह कहना भी मुश्किल है।

सेमिनार में मौजूद डॉ. सुबेश दास, अभिजीत सेन व अन्य वक्ता।

रोजगार मिले, तो मंदी का असर नहीं कहा जाएगा : प्रो. झा

जेएनयू के प्रो. प्रवीण झा ने कहा कि वैश्विक मंदी को देखें और देश में रोजगार के अवसर हैं, तो इसे मंदी का असर नहीं कहा जाएगा। वैश्विक मंदी की तुलना में देश की ग्रोथ रेट खराब नहीं है। झा पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदी को आजीविका और रोजगार से जोड़ कर देखते हुए योजना बनाने की जरूरत है। आज देश में आजीविका और रोजगार दोनों चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है, उससे देश में रोजगार के नए क्षेत्र भी विकसित होंगे। यहां युवा कौशल की कमी नहीं है। जरूरत है सही मार्गदर्शन का।

बुद्धिजीवियों ने रखे विचार

डॉ. सिमिन मुहम्मद बीआरएसी विवि, बीआरएसी डवलपमेंट इंस्टीच्युट बांग्लादेश, डॉ. बंदिता सिज़ापति, प्रोफेसर नेपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एवं ह्युमिनिटी, काठमांडू नेपाल, डॉ. केपी कान्न निदेशक, सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज, डॉ. हरीश गजादर, सीनियर रिसर्च, कलेक्टिव फॉर सोशल साइंस रिसर्च सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च, कराची पाकिस्तान, डॉ. रमानी गुंटिलका, कोलंबो विवि, श्रीलंका, डॉ. शेर वरीक सीनियर इंप्लायमेंट स्पेशलिस्ट आइएलओ वर्क टीम और प्रो. निशा श्रीवास्तव डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, इलाहाबाद ने अपने विचार रखे।

कृषि का ट्रेंड चेंज कर आर्थिक विकास संभव : रिजवानुल

भास्कर संवाददाता | रांची

इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तेलंगाना और इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन डेवलपमेंट नई दिल्ली की ओर से ट्रांसफॉर्मेशन इन रुरल इकोनॉमी एंड इंप्लायमेंट ऑपरच्युनिटीज इन इस्टर्न इंडिया विषय पर बुधवार को सेमिनार हुआ।

सेमिनार का आयोजन बूटी मोड़ स्थित होटल रॉयल रिट्रीट में आयोजित किया गया था। प्रोफेसर अभिजीत सेन (प्लानिंग कमीशन के पूर्व सदस्य) ने सेमिनार की अध्यक्षता की। कार्यक्रम दो सत्रों में हुआ। दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉ. सुबेश दास (प्रधान सचिव प्लानिंग एं बंगाल सरकार) ने किया। सेमिनार में आईएचडी इस्टर्न रीजनल सेंटर के निदेशक डॉ. हरिश्वर दयाल और रिसर्च प्रोग्राम की डायरेक्टर डॉ. मितिया बंटीलेन द्वारा रिसर्च प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

आईएलओ के पूर्व विशेष सलाहकार रिजवानुल इस्लाम ने अपना रिसर्च लेख प्रस्तुत किया। उनके लेख में नीड फॉर रिथिंकिंग डेवलमेंट स्ट्रेटजी और वीमेन वर्क एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ इंडिया का जिक्र था। रिजवानुल इस्लाम ने कहा कि आर्थिक विकास से रोजगार उत्पन्न होता है। कृषि आधारित व्यवसाय का ट्रेंड चेंज कर आर्थिक विकास संभव है। ग्रामीण पलायन रुकेगा। आईएचडी निदेशक प्रो. अलख नारायण शर्मा ने सोशल एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट इन बिहार : ऑपरच्युनिटीज एंड चैलेंजेज पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि बिहार धीरे-धीरे प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। बिहार में एक-दो जिले ऐसे हैं, जिसके गांव शहर का रूप ले चुके हैं। यहां मजदूरों का पलायन रुक

बिहार में चेंट हुआ ट्रेंड

प्रो. डी नरसिंहा रेडी ने कहा कि बिहार के कुछ गांव ने ऐसा विकास किया जो शहरी को पीछे छोड़ दिया है। ग्रामीण यहां के ट्रेंड कृषि कार्य से मन हटाकर नन फॉर्मल एक्टीविटी में बढ़ने लगे हैं। ऐसे एक्टीविटी यहां के आर्थिक विकास को मजबूत कर रहे हैं। प्रो. देवनाथन ने इस्टर्न इंडिया में आदिवासी विकास एक चुनौती पर विचार रखे।

गया है। जो बाहर रह रहे थे वो भी वापस आ रहे हैं। नन फॉर्मिंग कार्य पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है।